SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR EXPENDITURE OF THE GOVERNMENT OF MANIPUR, 1993-94.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : Madam, I beg to lay on the table a satement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants for Expenditure of the Government of Manipur for the year 1993-94.

THE BUDGET (MANIPUR), 1994-95.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : Madam, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) of the estimated receipts and expenditure of the Government of Manipur for the year 1994-95.

STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE AIR CORPORATIONS (TRANSFER OF UNDERTAKINGS AND REPEAL) ORDINANCE, 1994 (NO. 4 OF 1994)

THE AIR CORPORATIONS (TRANSFER OF UNDERTAKINGS AND REPEAL) BILL, 1994.

THE DEPUTY CHAIRMAN : We now take up the Statutory Resolution seeking disapproval of the Air Corporations (Transfer of Undertakings and Repeal) Ordinance, 1994 (No. 4 of 1994) promulgated by the President on the 29th January, 1994. and the Air Corporations (Transfer of Undertakings and Repeal) Bill, 1994. Shri Jethmalani.

SHRI RAM JETHMALANI (Karnataka : I have decided to withdraw my opposition So, I am not moving this Statutory Resolution

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Uttar Pradesh) : The next man will move

THE DEPUTY CHAIRMAN : Shri Maheshwar Singh.

SHRI MAHESHWAR SINGH (Himachal Pradesh) : Madam, I move the following Resolution :

"That this House disapproved of the Air Corporation (Transfer of Undertakings and Repeal) Ordinance, 1994 (No. 4 of 1994) promulgated by the President on the 29th January, 1994."

[The Vice Chairman (Shri MD Salim) in the Chair]

उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन में इस आर्डिनेंस का विशेष विरोध करना चाहूंगा । उपसभाध्यक्ष महोदय, आज यह सरकार एक आर्डिनेंसज की सरकार बनकर रह गई है । यह रिकार्ड सिद्ध करता है कि 29 जनवरी, 1994 को मन्त्री महोदय ने अध्यादेश जारी करके 1953 का जो एयर कार्पोरेशंस एक्ट था, उसको रिपील किया है । महोदय, इससे पूर्व मंत्री महोदय 27 अप्रैल, 1992 में दूसरे सदन में इस विधेयक के अमेंडमेंट को प्रस्तुत कर चुके थे, उस पर केवल मात्र चर्चा नहीं हुई थी और ठीक एक साल नौ महीने के बाद सरकार जागी । अगर यह आर्डिनेंस इतना आवश्यक था तो सरकार समय रहते आर्डिनेंस जारी कर देती । लेकिन एक साल नौ महीने न तो सरकार उस अमेंडमेंट पर चर्चा करवा सकी और न उस सदन में चर्चा हुई । मेरे ख्याल से यह संसदीय परम्पराओं के इतिहास में पहला मौका है कि जब किसी सदन के विचारार्थ कोई अमेंडमेंट हो और सरकार दूसरी तरफ अध्यादेश जारी कर दे । मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं । महोदय, मैं उधर बैठे हुए साथियों को एक बात यह भी बताना चाहूंगा कि जब पंडित जवाहर लाल नेहरू इस देश के प्रधानमन्त्री थे तो 1950 में माननीय मावलंकर जी, जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इन आर्डिनेंसेज का विरोध किया था और उस समय पार्लियामेंटरी अफेयर्स के मन्त्री को एक पत्र लिखा था जिसको मैं यहां क्वोट करते